खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ): उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Religious and Endowment Institutions

5573. SHRI N. SHIVAPPA: Will the Minister of LAW be pleased to state:

(a) the number of Regional Offices and their Head Offices for Religious and Endowment Institutions in the country;

(b) whether there are any Regional Offices, State-wise;

(c) whether there is any Regional Office for Mysore State; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) to (d). There is no provision in any Central law for the establishment of Regional or Head Offices for Hindu religious institutions.

Under the Work Act, 1964 (29 of 1954), there is provision for a State Government appointing initially a Commissioner of Wakfs and as many Additional or Assistant Commissioners of Wakfs as may be necessary for the purpose of making a survey of wakf properties in the State. There is also provision for the establishment of a Board of Wakfs in a State and the constitution of the Central Wakf Council by the Central Government for the purpose of advising it in matters concerning the State Boards.

As regards charitable endowments, the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), provides for the Central Government appointing a Treasurer of Charitable Endowmens for India and each State Government appointing a Treasurer of Charitable Endowments for the State.

टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई

5574. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में टेलीफोन तथा तार प्रणाली क विकास के लिये बड़ी संख्या में टेलीफोन उपकरणों की सप्लाई के लिये गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त मांग पूर्णरूप से पूरी नहीं की गई है;

(ग) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने किन-किन तथा कितने उपकरणों के लिये अनुरोध किया था; और

(घ) उक्त अवधि में उन्हें कितने उपकरण दिये गये ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक टेलीफोन घर, संयुक्त कार्यालय, टेलीफोन केन्द्र खोलने तथा टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था करने जैसी विविध सुविधाओं के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति के माध्यम से पोस्टमास्टर जनरल, भोपाल को लिखा है ।

(ख) ऐसी माँगें यथासंभव पूरी कर दी गई हैं । साथ ही इस राज्य में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार करते समय भी इन माँगों को ध्यान में रखा गया है ।